method in which the papers should be reorganised. I am certain that without Government trying to draw their attention to the distortions that might be affected, if Shri Shyamnandan Mishra's apprehensions prove to be true, wisdom will prevail.

My hon. friend, Shri Mishra, said that to an extent, he has started suffering already. I think to an extent also some newspapers are doing so to use it as an arm-twist. I hope they will not try to do so.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I am on another issue, the issue which I raised last Friday when the Deputy-Speaker was in the Chair. I expected the hon. Minister of Industrial Development would make a statement today about the NTC's attitude and their decision to increase the price of cloth...

MR. SPEAKER: But there must be some intimation sent to me beforehand He should not abruptly get up and speak like this.

SHRI VAYALAR RAVI: I expected the Minister but he did not come. Please direct him to come here. (*Interruptions*). The Minister did not turn up.

MR. SPEAKER: Order, order. We will now resume discussion of the Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill.

12 50 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: We have only 30 minutes left out of the time allotted; how much time would the Minister like to take?

THE DEPUTY MINISTER IN THE THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): 15 to 20 minutes.

MR. SPEAKER: Then there is no use asking any other Member to speak. There is no chance for them.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I can cut it down to 10 to 12 minutes.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAGHURAMAIAH): There are yet two or three speakers.

MR. SPEAKER: 12 minutes is all right. I will give three or four minutes each to one or two Members. Now, Shri Daga.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । आ एक बात पर विचार कीजिये । पहले आप की कोआपरेटिव सोसायिटीज कोई स्कीम बनाती है, उस के बाद उस का एग्जामिनेशन होता है अपेक्स बैंक मे, और अपेक्स बैंक्स को फाइनेंस करता है ऐग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन। एक स्कीम को बनते हुए कितना समय लगता है ? पहले स्कीम का एग्जामिनेशन करती है स्टेट्स की कोआपरेटिव, उस के बाद अपेक्स बैंक उस की जांच करता है और उस के बाद वह ऐग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन में आती है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप कोई स्माल इंडिगेशन स्कीम बनाते हैं तब उसको रिफाइनेन्स करने में इतना समय क्यों लगता है कम से कम आप उस का

[श्री मूलचन्द डागा]

हिसाब तो बतलाइये । एक दो साल मे स्कीम तैयार होती है, फिर उस को रिफाइनेन्स करने मे कम से कम एक या दो साल लग जाते है । लेकिन उस के बाद भी वह ठीक से पूरी नही होती ।

मेरे सुनने मे आया है कि इरिगेशन स्कीम्स कई कई जगहो पर बनती है । इरिगेशन स्कीम्स इरिगेशन डिपार्टमेंट भी चलाता है, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स भी चलाता है, प्रो० शेर सिह यहा बैठे हुए है, उन का डिपार्टमेंट भी चलाता है, कैश प्रोग्राम भी चलते है । मै जानना चाहता ह कि यह ओवरलैपिग क्यो है । इरिगेशन स्कीम्स का चलाने के लिए आप का कम्यूनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट भी वर्क करता है, स्माल इरिगेशन डिपार्टमेंट भी वर्क करता है आप के यहा कैश प्रोग्राम्स भी चलते हे । फिर बैंक्स का नेशनलाइजेशन होने क बाद आदमी डाइरेक्ट लोन के लिये वहा जा सकता है । मैं आप से जानना चाहता हू कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन होने के बाद इस बिल की क्या आवश्यकता है । मेरी समझ मे नही आता कि आप का क्या तरीका है ।

इस विधेयक में एक बडा सुझाव यह है कि आज से उन लोगो को जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है, लोन मिलेगा । इस सम्बन्ध मे सब से बडा डिफेक्ट यह है कि जो रिफाइनेन्स करने वाले है वह ऐग्रीकल्चर के बारे मे नहीं जानते । स्कीम तो सारी ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है और पैसा देने वाले आप हैं । आखिर सारा पैसा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यो न दे ?

इस बिल के सम्बन्ध मे मै एक बात कहना चाहता हू । मैं जानना चाहता हू कि क्या देश के अन्दर एक भी सोसायटी लेबरर्स की बनाई गई और क्या उन को कर्जा मिला है । मैं कहता हू

Land has been been allotted. Now, can that man get a loan or not? The land was allotted and the patta has been issued. Even then, can that landless labourer get help from any source or not?

जो लैंडलेस लेबरर्स होते है उन का कोई रिकग्निशन नही होता है । उन को किसी कोआपरेटिव का बनने के बाद रजिस्ट्रेशन नही हुआ है । देश के अन्दर जितनी कोआपरेटिव सोसायटीज है उन का सारा काम आफिसो के तरीके पर होता है । जब तक उन मे आफिसो का अलिम बना हुआ है और वह हटता नही है तब तक काम नही चल सकता । अगर कोई भी छोटी सी गलती कर दे, कोआपरेटिव सोसायटी मे कुछ गडबड हो जाय तो सारा आफिस उस को ले कर बैठ जाता है । मेरे खयाल मे तो एलेक्शन भी कोआपरेटिव्ज के टाइम पर नही होने । आप यहा पर कोआपरेटिव्ज को बढाना चाहते है, उन के जरिये लोन भी देना चाहते है । ऐसी हालत मे पहला काम यह होना चाहिये कि कोआपरेटिव्ज के एलक्शन इन्स्टिटयूशन की तरह पर होने चाहिये और उस की मशीनरी अलग होनी चाहिये नही तो आप का काम नही चल सकता ।

दूसरी बात यह है कि जो आप के आफिसर्स है उन का इटरफिअरेस नही होना चाहिये । हर कोआपरेटिव सोसायटी के बाहर आप का इन्स्पेक्टर बैठा हुआ है जो उस को खा जाने के लिये मौजूद है । 100 गलतिया करते रहो और उन को खिलाते रहे तो कोई बात नही है, लेकिन अगर छोटी सी गलती हो जाय और कोआपरेटिव पैसा न दे तो उस का काम नही चल सकता । जितने भी कोआपरेटिव बैंक्स हैं उन के साथ आफिसर्स का जो सम्बन्ध है वह टूट जाना चाहिये । जितने ही कम आफिसर्स हो उतना ही अच्छा है । जितनी भी कोआपरेटिव सोसायटीज वर्क कर रही हैं उन के साथ आप के आफिसर्स लगे है, कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वह स्कीम्स का एग्जामिनेशन करते हैं । कभी आप गाव के अन्दर जा कर इन बातो को देखिये । जो

आप के लैंडलेस लेबरर्स को पैसा देने की स्कीमें है उन में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है ।

आजादी के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर स्माल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत हो गये । गावो के अन्दर कुछ लोगो के हाथ मे दौलत आ गई । गरीब गरीब ही रहे और मालदार और मालदार बन गये । आप किसी भी गाव मे चले जाये, जिन्होने किसी तरकीब से पैसा हडप लिया उन्होने हडप लिया और जो गरीब है वह और गरीब बन गया । पच्चीस साल के बाद भी जो पहले आखिरी पक्ति मे खडा हुआ था वह आज भी आखिरी पक्ति मे खडा हुआ है ।

मै इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हू, लेकिन इस रिफाइनेन्स कारपोरेशन मे एक बात है । जो इस म डाइरेक्टर लोग है उन मे हमारे रिप्रेजेन्टेटिव कितने है ? सारा की सारी मशीनरी उप के अन्दर गवर्नमेंट की है । हम लोगो की आवाज उस मे बहुत कम है । वहा पर सब एम्प्लायीज गवर्नमेंट के है । मै जानना चाहता हू कि आखिर आप पावर का विकन्द्रीकरण करना चाहत है या सेंट्रलाइजेशन करना चाहते है ? किसी भी स्कीम के लिये आदमी को आप के पास आने की जरूरत क्या है ? गावो के अन्दर जो स्कीम आप की है उन के लिये स्टेट लेवेल पर लोन मिल जाना चाहिये क्योकि आप के पास आने मे तो दो दो साल लग जाते है । ऐसी स्थिति मे इस बिल का परपज हल नही होता ।

SHRI RANABAHADUR SINGH (Sidhi): I welcome this amendment. My only submission is that the pace at which the ARC is being tailored to the needs of the rural credit is a bit slow. Last time an amendment was passed in this House on July 31, 1971 It has taken almost two years for the next move to be made. I think that at this rate of ARC will remain hanging in the air and it will take a very long time for it to be meaningful in meetings the needs of rural credit. I suggest that apart from this amendment, Government take very urgent steps to bring about procedural simplification in their ways of giving loans to schemes in the rural areas.

13 hrs.

One of the things I would like to mention in this context is that one scheme was sanctioned by the ARC for electrification of pumps in the rural areas and digging of wells. Fortunately, for an area which fell in that unit there was a perennial stream running through that village So, the villagers wanted to use electric pump without digging the well It was a mortification for the villagers when they were told that since the ARC had sanctioned the scheme for wells and pumps, they would not give any loan only for pumps, in spite of the fact that water was available in the stream. I would say that cases like this are proof enough that the ARC is not in touch with the rural credit needs, and that is what I mean when I say that procedural simplifications are called for.

I would also plead that the consutancy services that have been set up by the ARC at present are limited to the eastern sector of the country. They should be more widely spread It is my request that a consultancy service centre must be opened in Bhopal to cater to the widely divergent needs of a large State like Madhya Pradesh, specifically because out of the Rs. 30.62 crores that have been funded by the ARC so far, Madhya Pradesh has received only Rs. 91 lakhs

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I would like to thank all the hon. Members who have participated in this debate. I think, by and large. this Bill has

been unanimously supported. I welcome the suggestions that have been made.

MR. SPEAKER: She may continue her speech after lunch. The House stands adjourned till 2 O'Clock.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Sushila Rohatgi to continue her speech....

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम और जरूरी सवाल की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

अभी अभी मंत्री महोदय ने लोको स्ट्राइक के बारे में बयान दिया है । लोको की स्ट्राइक समाप्त हुई, उस पर हम सब लोगों को खुशी हुई है । लेकिन राजस्थान में एक महीने से अधिक समय से हड़ताल चल रही है । टीयरगैस का हमला हो रहा है और लाठियां चल रही हैं। सैकड़ों लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया आप कह सकते हैं कि यह राज्य का मामला है । लेकिन आखिर सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं ? जरूरत की चीजों का अभाव है, दाम आसमान को छू रहे हैं, जिस के लिए केन्द्र जिम्मेदार है । यहां के गृह मंत्री, श्री राम निवास मिर्धा, का राजस्थान से सम्बन्ध है । क्या वह राजस्थान की सरकार और वहां के सरकारी कर्मचारियों में बीच-बचाव कर के इस हड़ताल को समाप्त कराने का प्रयास करेंगे ? संसदीय-कार्य मंत्री यहीं पर बैठे हुए हैं । वह हमारी भावनाओं को श्री मिर्धा तक पहुंचा दें कि वह राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने, और कोई समझौता कराने का प्रयास करें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहले भयंकर सूखा पड़ा था और अब वहां भयंकर बाढ़ आ गई है । हम चाहते हैं कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या बहस को स्वीकार किया जाये, ताकि हम लोग अपनी समस्याओं को यहां पर रख सकें । उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रपति शासन है । हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये ।

14.07 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, I will start by thanking all the hon. members for their valuable suggestions. It is only natural that, in the course of the discussion of this Bill, the functions, the operations, the objectives and the entire working of the various financial institutions should have been discussed, whether they are directly or indirectly concerned with refinance.

So far as this particular Amendment Bill is concerned, it relates to only refinancing and has the limited objective of augmenting the resources which are available to the financial institutions with a special eye on encouraging, and on alleviating the miseries of, those people who are small farmers, who are agricultural labourers and those who have no land whatsoever. All the hon. members, irrespective of their party affiliations, have appreciated this objective.

[Shrimati Sushila Rohatgi]

I would only like to allay the fears and apprehensions expressed by Shri Bhogendra Jha, who is not present here now. He had some apprehension that this might be utilised in a manner which would be detrimental to the very objective. I would like to assure him that that is not the purpose. In fact, the various suggestions that have been made by the various speakers would be taken into consideration, and where there are difficulties, where there are obstacles, where there are impediments in the way of proper operation, I would assure them that we shall look into the matter.

Now I wish to draw the attention of the hon. members to the work done by the ARC. It is true that, in the first four years, the work was not as good as it should have been. Anything in the offing takes a little time to walk on its own feet. But since 1968 the working of the ARC has been appreciable. I am happy to tell the members—and they are aware of this fact—that at present 888 schemes have been sanctioned by the ARC and the financial outlay comes to Rs. 524 crores And they are at various stages. But I would like to clarify one point. It was asked by an hon. Member as to why the disbursals are slow and why the money is lying unutilised. There is no question of money lying unutilised because the money is sanctioned for the entire project, and it is phased out in various stages. After a certain phase of the project has been completed and if more money is needed for refinancing, the requisite finance is given. Therefore, there is no question of unutilisation and no project is held up because of finance whatsoever, because the sanction is for the entire project as a whole.

The present picture is: out of 888 schemes—I would also like to give the break-up for the information of the hon. Members—about 60 per cent of these schemes are concerning minor irrigation which are of extreme importance to the country as a whole.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): Would you just lay on the Table the various schemes and the stages at which they are now for the information of the hon. Members so that we may be enlightened?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I would be very happy to do that. Apart from that, if I may take your indulgence for a minute, I would draw your attention that out of 888 schemes, a major part, nearly 60 per cent has gone to minor irrigation. They account for 536 schemes. Land development, tractors and power-tillers, soil conservation, plantation, poultry farming, fisheries, dairy development and for construction of godowns, silos, marketing yards and sheds. These are the major schemes. I have got the exact number and the amount utilised and I would be very happy to pass it on to the members

Some members have mentioned that there is a lot of delay for according sanction. One hon. Member mentioned that it takes years and takes a long time for any scheme to be really sanctioned and, therefore, this delay factor must be eliminated. I would like to clarify this point. There is no question of delay. In the beginning there was some delay, but now, the refinancing part with which this Bill is cocerned, does not take any time at all. for at the time of the formulation of the scheme itself, all these agencies—the State Government, the Co-operative Bank, the commercial bank and the ARC discuss it and they work as a team and once any particular institution which is financing or the Agricultural Refinance Corporation accepts the scheme, whether it be the co-operative bank or the commercial bank, it goes ahead with the work of financing these schemes and the refinance is done even at a later stage. It is not because of the ARC that any work

on these particular schemes is held up and, therefore, the delay factor is not the responsibility of ARC. Even otherwise, there is scope for improvement and certainly we welcome the suggestions given by the hon. Members.

I am very happy to state that the Consultancy Service which has been instituted with its head office at Lucknow has done good work and in the immediate future we are starting a consultancy office at Calcutta also. So far 76 schemes have been finalised through this consultancy service. I have also got the break-up here. They are in various States. In Assam we have 6 schemes. in Bihar 6, Meghalaya 7, Orissa 14, West Bengal 17 and West U.P. 26. These are the schemes which have been really sponsored through the consultancy service which has done so much in the course of less than two years. Therefore, another office is to be set up at Calcutta.

Certain allegation was, however, made by an hon. Member from Tamil Nadu. He said that there is a discrimination and he asked why a consultancy centre was not set up in Tamil Nadu. I may tell him that no work in Tamil Nadu has suffered because of it and Tamil Nadu is able to look after itself very well. It is only the Eastern districts and North-eastern districts because of lack of infra-structure and other conditions are not able to do very well. Therefore, it is giving a momentum for their development.

I shall quote the figures about the Tamil Nadu to clear up if there is any lack of coordination. A point has been made invariably by all the Members and do feel that this is a relevant point and there is, to some extent, regional disparity which still exists. I feel that the regional disparity still exists in the places from where you and many of the Members come from. All of them realise that this regional disparity must be removed. If not immediately, they must at least be mitigated at the earliest. I am glad to say that the Government being aware of this, especially, the A.R.C. being aware of this, to-day, has taken certain corrective steps in this direction. The steps that are taken in this regard are: special meetings had been convened or sponsored by the A.R.C. between the Agriculture Ministry—they are convened at the invitiative by the Agriculture Ministry—and the State Governments. They have involved the State Governments—their representatives—and various financing agencies and they have reviewed the various difficulties and impediments that stand in the way. We hope that they will try to prevent or remove the regional disparities. On the basis of certain suggestions that have been made here, the Finance Minister himself had called a meeting of ten States and their Agricultural Production Commissioners and had talks with them and other States' representatives. On the basis of these meetings, a number of steps had been taken. As a consequence, it has been decided that where the cooperative societies are weak, they must be strengthened; thre must be greater coordination between the various financial institutions. Also there must be greater coordination between the State Governments and various project authorities and various financial institutions. The recommendations of the Talwar Committee would be implemented as early as possible.

Apart from that, now, we have regional offices in almost all the States. In Gauhati also, a centre has been opened. Therefore, almost all these States are really covered; their working is looked after by the regional officers. Apart from that, some State Governments have special cells also which are looking after specifically the schemes to be sponsored for A.R.C Some of the schemes fall under the S.F.D.A.—Small Farmers Development Agencies. Almost all State Governments are trying to sponsore schemes for small farmers—

[Shrimati Sushila Rohatgi]

marginal farmers—who are the vulnerable weaker sections. A.R.C. even gives them 100 per cent re-financing for these vulnerable sections of the society which will indeed be a step in that direction. Members would like to have the break-up of the various schemes in various States. I would like to point out here that because of various steps that had been taken, there has been progress made by the S.F.D.A. in regard to small and marginal farmers' requirements. The break-up as on 30th June, 1968 was as follows:

In Assam, they were four. Let me first tell you that the total number of schemes at the end of January, 1968 was 128 in all the States. The A.R.C's schemes have been increased from 128 to 888 and their outlay has also been increased to Rs. 524 crores. About the details of the small and marginal farmers, the position as it stands now is as follows:—

Number of Schemes
As on 31-5-1973

Andhra Pradesh	3
Haryana	1
Himachal Pradesh	1

The total number comes to 36. Finacial assistance is of the order of Rs. 39.71 crores—this is for the small and marginal farmers. I am not saying that this is precisely the reason why the Bill is coming up. That is because the banks and the cooperatives have really taken the initiative on this. It is because of them that so many schemes have come up. After all, the A.R.C. have also play their role in the matter of preparation of techno-feasibility report for the schemes. In this context, we would like much more resources to be placed at the disposal of the small farmers and the marginal farmers.

At present, you aware there is a certain legal difficulty according to which financing cannot be done without mortgage of land or government guarantee. That is a delaying process and acts as a bottleneck. If the Bill is passed, this difficulty will be removed and it will permit of much greater resources being available for refinancing, resources which would be placed at the co-operative and commercial banks.

As for the future, we have a great future. The basic approach of the ARC is to give the maximum possible support subject to financial constraint to the small farmers to the people who are really needy, and also to remove regional disparities. For this a number of suggestions have been made. Government are considering all these. I will not take the time of the House on this. An interim report has also been presented by National Commission on Agriculture. Government would study all these facts. I am happy to say that with the help of IDA a number of schemes have been taken up in various States. Because of the good work done by ARC today, the IDA is also helping them and the fact that IDA should be prepared to sanction a direct line of credit speaks highly of the work of the ARC.

With these words, I thank hon. members and hope they will pass the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause by clause consideration.

There are no amendments. The question is:

"That clauses 2 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI. I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR DEPUTY-SPEAKER Motion moved.

"That the Bill be passed"

श्री मधु लिमये (बांका) उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के उद्देश्य से मैं सहमत हूं। लेकिन सवाल यह है कि जो संशोधन हमारे सामने आया है उस का इस्तेमाल कैसे होगा? यह जो रीफाइनेन्सिंग कारपोरेशन है, यह तो किसी भी योजना पर स्वयं अमल नहीं करता। योजनाओं पर अमल करने वाली संस्थायें दूसरी हैं, कोआपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड डवलपमेन्ट बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड और कार्मशियल बैंक्स हैं, इन संस्थाओं के द्वारा योजनाओं पर अमल होना है और मैं यह कहने के लिये बाध्य हू कि राष्ट्रीयकरण के बाद इन सस्थाओ के दृष्टिकोण मे काई बुनियादी फर्क नही आया है। मैं आप ही की इस किताब से कुछ वाक्यो को उद्धृत करना चाहता हू—सारी योजनाओ का आधार है—सिक्योरिटी, इस छोटी सी पुस्तिका मे जो आप की किताब है—कहा गया है—

Agricultural Refinance Corporation: Functions and Working

"Schemes sanctioned in respect of scheduled commercial banks: the securities to be sub-mortgaged/hypothecated by the ultimate borrower in favour of the financing bank and refinances provided to the extent of 50 per cent of the value of the securities".

आगे दूसरे अनुच्छेद मे कहा गया है—

"The cultivators to be financed under the schemes should be those who have mortgageable or alienable rights over their holdings which are proposed to be mortgaged to the financing institutions Further, the cultivators should preferably contribute a part of the funds required from their own resources to the extent possible with a view to ensuring that they take keen interest in the schemes evolved for their benefit"

अब उपाध्यक्ष महोदय संथाल परगना, जिस का एक क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र के नीचे आता है उस मे— मंत्रिणी जी की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां का कानून अपनी जमीन को आदिवासियों को देने की छूट नही देता है, ऐसी स्थिति मे उन के पास "एलीनियेबिल जमीन" नही है

श्री जगदीश नारायण मंडल (गोड्डा) संथाल परगने मे खाली आदिवासी ही नही, गैर-आदिवासियो की जमीन भी बन्धक नही होती है। बैंको से उन को कोई लाभ नही है.

श्री मधु लिमये इस समय जो संथाल परगने का कानून है, मैं उस की बात कर रहा हू, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिये बिल रखा है। आदिवासी इस भूमि कानून के तहत अपनी जमीन नही बेच सकता, इस लिये उन को इस का फायदा नही मिलता है, क्योंकि "एलिमियेबिल लैंड" उन के पास नही है, कानून से गिरवी नही रख सकते है, न सम्पत्ति है जो गिरवी रख सके, न जमीन है जो गिरवी रख सके—ऐसी स्थिति मे संथाल परगने के जो गरीब किसान हैं, उन की समस्याओ पर भी विचार होना चाहिये।

दूसरी बात—यह जो सिक्योरिटी वाली बात है, मेरी समझ मे नही आता, जब छोटे किसानो का सवाल आता है तो ये बैंक वाले, खास कर कार्मशियल बैंक वाले पचास किस्म

[श्री मधु लिमये]

के झगड़े डालते हैं और लैंड डेवलपमेन्ट बैंक और स्टेट कोआपरेटिव बैंक का जहां तक सम्बन्ध है, उस पर बड़े जमींदार और बड़े काश्तकार हावी है, इसलिए छोटे किसानों को इन सारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता ।

लेकिन जो कामर्शियल बैंक है, जिन का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उन का पूंजीपतियों के साथ व्यवहार कैसा है ? वास्तव में इन व्यापारिक बैंकों और पूंजीपतियों के घरानों का जो गहरा रिश्ता था, जिस के चलते बैंकों के साधनों का इस्तेमाल पूंजीपति अपनी सम्पत्ति को और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिये करता था, उस से मुक्ति दिलाने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये, इस सदन में हम ने कई संशोधन दिये थे लेकिन एक संशोधन के अलावा दूसरा कोई संशोधन नहीं माना गया । कर्मचारियों के प्रतिनिधि लेने की बात है, काश्तकारों के प्रतिनिधि लेने की बात है लेकिन हो क्या रहा है? सुशीला जी जिस इलाके से आती है,—उस कानपुर की एक घटना के बारे में बतलाना चाहता हूं —कानपुर, नया गंज में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है । आप को आश्चर्य होगा, यह शाखा जे० के० ग्रुप की एक शाखा के रूप में काम करती है, यह राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, यह जे०के० ग्रुप की शाखा है और आज जे०के० ग्रुप में इतनी उद्दण्डता आ गई है कि नया गंज बैंक के मैनेजर को वह पत्र लिखते हैं—मैं एक पत्र का नमूना लाया हूं और आप की सेवा में प्रस्तुत करता हूं । आप पूछेंगे कि रीफाइनेन्सिंग से इस का क्या सम्बन्ध है ? मैं दो दुनियाओं की तस्वीर आप के सामने खींचना चाहता हूं—एक ओर संथाल परगने के आदिवासी और छोटे किसान हैं, जिन के पास खेती के लिये जमीन नहीं है, जिन के पास सम्पत्ति नहीं है, उन की क्या हालत है और दूसरी तरफ इन बड़े लोगों की क्या हालत है । यह पत्र 9 मई, 1973 को जे०के० रेयोन ने पंजाब नैशनल बैंक, नया गंज शाखा को लिखा है—

"Dear Sir,

Consignment of 6,672, bales of wood pulp by SS Viswabhakti

We have to inform you that the above consignment has been imported by us and the ship is touching Calcutta port on or about the 15th instant We require a sum of Rs 11,20,000 to clear the said consignment from the port You are requested to kindly take the above 6,672 bales of wood pulp under pledge with you and issue us a bank draft for Rs 11,20,000 in favour of Messrs Calcutta Shipping Bureau payable at your Calcutta counterpart and your charge in this connection may please be debited to our account with you For your information, we may add here that the cost of 6,672 bales of wood pulp comes to Rs 44,03,520, that is, at Rs 660 per bale The BP comes to Rs 33,02,640 Yours faithfully"
"Please issue draft"

उसके नीचे मैनेजर का नोट है—

इस में खूबी क्या है? जो माल आ रहा है, जिस को ये गिरवी रखना चाहते हैं, वह समुद्र पर है, विश्व-भक्ति जहाज समुद्र पर है, वह माल अभी कलकत्ता नहीं पहुंचा है, कानपुर आते-आते दो महीने लगने वाले हैं, माल आयेगा या नहीं आयेगा, इस का पता नहीं है, हो सकता है विश्व-भक्ति डूब जाय, लेकिन जो माल इन के कब्जे में नहीं आया और इन के गोदाउन में नहीं पहुंचा है, दो महीने के बाद पहुंचेगा, उस के लिये ये लोग 11 लाख 20 हजार रुपया—दो-तीन हजार रुपया नहीं—मांगते हैं । और मैनेजर लिख देता है इनको दे दिया जाये । कितने दिनों में क्लियर होता है?

चार दिनो मे ड्राफ्ट मजूर हो जाता है। सोचने की बात है कि जे०के० के लिए जो लिमिट दी गई है उस एकाउन्ट मे क्या उसको

SHRI K P UNNIKRISHNAN (BADAGARA): Sometimes the banks are also very efficient

श्री मधु लिमये इसीलिए आप देख रहे है कि चार दिन मे मजूर हो जाता है। आश्चर्य की बात है इस एकाउन्ट के लिए जो लिमिट निर्धारित की गई थी उसको भी एक्सीड करते है जे०के० रेयान वाले। और क्या क्या करते है उस के बारे मे वित्त मत्री का मैने पत्र भी लिखा है। तो चकि मैनेजर की इसके ऊपर नोटिंग है इसलिए आपकी आज्ञा से यह कागज सभा-पटल पर मैं रखना* चाहता हू। इसको आज आप इजाजत दे ताकि अखबार वाले खूब अच्छी तरह से उसका छाप सके।

इसके साथ साथ दो बातो को मै और जोडना चाहता हू। मैने कोई इर्रेलेवेन्ट बात नही कही है। सारे कानूनो को तोड कर, जो माल समुन्दर मे हो, जो उनके गोडाउन मे आया तक नही है, कोई बिल आफ लेडिग नही है, उसके अगेन्स्ट चार चार दिन मे 11 लाख 20 हजार रुपया मिल जाता है। तो अभी आपने जो सशोधन रखा है क्या उसकी तहत चार दिनो मे गरीब किसानो, आदिवासियो, खेतिहर मजदूरो के जो लोन के लिए आवेदन-पत्र आयेगे उनको मजूर करवाने की कोई योजना होगी? क्या शेडुयल्ड बैंक्स, स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेन्ट बैंक्स को जरा सहानुभूतिपूर्वक दृष्टि से उन आवेदन-पत्रो पर कार्यवाही करने के लिए कहा जायेगा? यदि नही, तो मै कहूगा कि आपका यह सशोधन धोखाधडी है जैसे कि 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण एक बडा धोखा साधारण जनता के साथ हुआ। यदि आपके मेरे सभी सशोधनो को माना होता और जो—भ्रष्ट लोग है उन पर कडी कार्यवाही की होती तो मेरा खयाल है आज यह नौबत नही आती।

MR DEPUTY-SPEAKER: You may give the paper to me I have not given permission for laying it

श्रीमति सुशीला रोहतगी मान्यवर, मै माननीय सदस्य की बडी आभारी हू कि इस प्रकार की किसी घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके सम्बन्ध मे मुझे कोई पूर्व सूचना नही है परन्तु आपके माध्यम से मैं इतना विश्वास दिलाऊगी कि यह जो चीज है, जैसा उन्होने कहा है इस आरोप को देखा जायेगा, इसकी जाच की जायेगी और जो भी होगा वह माननीय सदस्य को अवश्य सूचित कर दिया जायेगा। चाहे कानपुर का नयागज हो चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो या कोई भी बैंक हो उनमे कोई भी अन्तर नही है। एक ही नीति है और उसी के आधार पर, उन्ही डायरेक्टिव्ज के आधार पर जितने देश का राष्ट्रीयकृत बैंक्स है उनको काम करना है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि चार दिन मे इन चीजो को हटाकर कार्य पूरा किया है

श्री मधु लिमये कानूनो को तोडकर किया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी आज उन कानूनो का परिवर्तन करके हम किसानो को मदद देना चाहते है। यह बात मैं स्पष्ट करना चाहती हू कि शुरू मे जब बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस वक्त आपके मन मे जो सशय होगा उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। इन बैंको के माध्यम से जितना रुपया दिया जा रहा है. . .

श्री नवल किशोर शर्मा : लैंड मार्टगेज बैंक्स की [illegible] प्रोसीजर को जब तक

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the paper was not treated as laid on the Table.

[श्री नवल किशोर वर्मा]

नही बदलगे तबतक कर्जा नही मिल सकता है ।

श्रीमति सुशीला रोहतगी हमने पहले भी ध्यान मे रखा था और आगे भी रखेंगे । राष्ट्रीयकृत बैंक्स जो है वह आपके विचार मे सफल नहीं हो रहे है लेकिन हमारे विचार मे सफल रहे है । यह बात अवश्य है कि उनमे अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है । (व्यवधान)

मै मजुलिमये जी से कहना चाहती हू कि मैने बड़ा शांति से आपकी बात सुनी है । मैने कहा है जबतक इसका खडन नही होता, जब तक मुझे इसकी जानकारी न हो तबतक मैं कुछ कहने की पोजीशन मे नही हूं । अवश्य इस बात की जानकारी होनी चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a lady appeals for sweetness, you must respond.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Thank you, Sir. I am sure he will respond.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है उसपर मै विशेष बल देना चाहती हूं । अभी तक जो दिक्कत रही है सेक्योरिटी की, मार्गेज की उसको हटाने के लिए यह बिल आया है । आपकी और हमारी राय में किसी तरह की भिन्नता नही है, जो आपके विचार है वही हमारे विचार है । इसलिए जो आपने कहा है, अगर आज वह हो जाता है जो सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है जिससे लीगल कठिनाइया उत्पन्न होती है उनका आसानी से समाधान कर सकेंगे और जो गरीब हैं चाहे वह संथाल हों या आदिवासी हों, गरीब की कोई अलग से जेब कटा नहीं होती, वह गरीब चाहे किसी भी प्रदेश का हो, उसके पास जमीन है या नही या जो लैंडलेस लेबरर है उसको सारी रिफाइनेन्स की फेसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए । इसलिए मै आपको विश्वास दिलाती हू। मार्गेज को हटाने और सेक्योरिटी को रिलैक्स, लिबरलाइज करने के लिए यह बिल आया है ।

दूसरी सारी बात जो है उनके सम्बन्ध मे पहले ही कहा जा चुका है इसलिए मै समझती हू इस बिल का पूरी तरह से जोरदार समर्थन होगा ।

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

14.35 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL), 1973-74

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up Supplementary Demands for Grants (General).

DEMANDS No. 11—FOREIGN TRADES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,28,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 74,00,00,000 on Capital Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of 'Foreign Trades'."

*Moved with the recommendation of the President.